

(c) There is already a jewellery gallery established in National Museum, New Delhi. These items of jewellery are being kept for display in that Museum, for public view.

Corruption in Delhi University

1782. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have made any study of the Book "The Drunk Tantra" by Dr. Ranga Rao highlighting the corruption and malpractices in the Delhi University and most of its affiliated colleges;

(b) if so, what is the reaction of Government with regard to the various ills of the Delhi University and the scenario in most of the colleges;

(c) whether Government propose to set up a high level committee to go into the various issues raised in the book; and

(d) if so, what steps have been taken by Government in this regard and if not what are the reasons for not going in depth about the functioning of Delhi University?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE (KM. SELJA): (a) The Government in the Ministry of Human Resource Development (Department of Education) has no information about the book in question.

lb) to (d) Do not arise.

विदेशों में अध्ययनरत छात्र

1783. श्री गोपाल सिंह जी साँझी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में उच्च तथा तकनीकी अध्ययन

के लिये बाहर भेजे गये छात्रों की राज्य-वार संख्या किन्ती है;

(ख) इनमें से किन्ते छात्र अपना अध्ययन पूरा करके स्वदेश लौट चुके हैं;

(ग) किन्ते छात्र अपना अध्ययन पूरा करने के बाद अभी भी विदेशों में ही रह रहे हैं;

(घ) अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले प्रत्येक छात्र पर सरकार द्वारा किन्ती औसत धनराशि खर्च की गई; और

(ङ) किन्ते छात्र अपना अध्ययन पूरा करके वापस आये और रोजगार प्राप्त करने में सफल हुए?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): (क) छात्रों की एक बड़ी संख्या स्वयं उच्च अध्ययनों के लिये विदेश जाते हैं। उनके बारे में सूचना एकत्र करना और रखना सरकार के लिए सम्भव नहीं है।

जहाँ तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग में सरकार का संबंध है, यह केन्द्रीय सरकार/विदेशों द्वारा प्रदत्त कुछ छात्र-वृत्तियाँ/अध्यता-वृत्तियाँ संचालित करती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत उच्च अध्ययन/तकनीकी शिक्षा के लिए 450 छात्रों को विदेश भेजा गया। शोध-छात्रों का चयन अखिल भारतीय आधार पर किया जाता है, न कि राज्य के आधार पर।

(ख) और (ग) उक्त 450 छात्रों में से 85 छात्र अपना अध्ययन पूरा करके वापस आ गये हैं। अन्य छात्रों को अपना अध्ययन पूरा करने के पश्चात् वापस आने की संभावना है।

(घ) कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई गई राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना (नेशनल ओवरसीज स्कीम) के अन्तर्गत किया गया औसत व्यय, विदेश में अध्ययनों के लिये प्रति वर्ष प्रायोजित 30 छात्रों के लिये प्रति छात्र प्रति वर्ष 7,06,530/- रु० (लगभग) है। शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विदेश में अध्ययनों के लिए अधिकांश छात्रवृत्ति योजनाएं, दाता देशों द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित हैं। कुछ मामलों में, सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अन्तर्गत, सरकार किराया/परफेक्ट अनुदान पर व्यय वहन करती है, जो प्रत्येक देश के आधार पर भिन्न-भिन्न होता है।

(ङ) विदेश से अपना अध्ययन पूरा करके वापस आये 85 छात्रों में से 50 छात्र पहले से ही अपने जाने से पूर्व सेवारत हो गये थे और वापसी आने पर रोजगार में लगा लिये गये। छात्रवृत्ति योजना में उच्च अध्ययन/अनुसंधान को सुगम बनाने पर बल दिया गया है।

Irregularities by National Open School

1784. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the grave financial irregularities being committed by NOS (National Open School) Officials;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the CBI has also seized the records of the NOS and found illegal deals in supply of substandard paper etc., and

(d) if so, what immediate action Government propose to take in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE (KM. SELJA): (a) to (d) It has come to the notice of the Government that

CBI has collected some files pertaining to the purchase of the paper from National Open School (NOS), an autonomous organisation under the Ministry of Human Resource Development (Department of Education), in connection with a preliminary enquiry. Further action against the delinquent official(s) of NOS, if so found after completion of CBI's enquiry/investigation, will be taken by the Disciplinary Authority under the external Rules and Bye-laws.

महिलाओं पर अत्याचारों संबंधी समाचार

1785. श्री दिग्विजय सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय महिला आयोग पर्याप्त अधिकारों के अभाव में पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने हेतु प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर रहा है;

(ख) क्या सरकार आयोग के समुचित कार्यकरण और पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने हेतु आयोग के अधिकारों में बढ़ोतरी करना चाहती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और दिनांक 6 और 7 जनवरी, 1995 के "दैनिक जागरण" में "महिला अत्याचार पर सार्वजनिक सुनवाई" शीर्षक से प्रकाशित समाचार पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासव राजेश्वरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जी नहीं। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990, के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग को अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाई जिसमें महिलाओं के लिए उपलब्ध सुरक्षापाथों से संबंधित सभी मामलों की छान-बीन